International Journal of Creative and Open Research in Engineering and Management
ISSN: **3108-1754 (Online)**
Volume 02 Issue 07 July-2026 | Impact Factor: 3.5

मध्यप्रदेश के विद्यालयों में खेल सुविधाओं की वर्तमान स्थिति : 2000 के बाद लागू खेल नीतियों एवं योजनाओं का मूल्यांकन

शोधार्थी - 'संजीव कुमार पाण्डेय (शारीरिक शिक्षा) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश

डॉ० संजीव मिश्रा, सहा०प्रा० शा०शि० विभाग अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म०प्र०)

शोध पर्यवेक्षक - डॉ. नीलम श्रीवास्तव प्राचार्या वैष्णवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन रीवा, मध्य प्रदेश

करस्पांडिंग आर्थर - प्रो. पवन कुमार पचौरी विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा एवं योग विभाग कुलभास्कर आश्रम पी.जी. कालेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

सारांश (Abstract)

यह शोध पत्र मध्यप्रदेश के विद्यालयों में खेल सुविधाओं (खेल मैदान, उपकरण, इनडोर / आउटडोर हॉल, व्यायाम शिक्षक तथा अकादमियाँ) की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन 2000 के बाद लागू प्रमुख खेल नीतियों (2005५ राज्य खेल नीति) तथा योजनाओं (खेलो इंडिया, Samagra Shiksha, Khelo MP Youth Games) के संदर्भ में करता है। द्वितीयक डेटा विश्लेषण (सरकारी रिपोर्ट, बजट दस्तावेज, नीति प्रावधान तथा अकादमिक अध्ययन) से पता चलता है कि पिछले 25 वर्षों में खेल सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिला स्तर पर सैकड़ों मिनी स्टेडियम, इनडोर हॉल तथा सिंथेटिक ट्रैक विकसित हुए हैं।

राज्य स्तरीय अकादमियाँ (एथलेटिक्स, शूटिंग, हॉकी आदि) स्कूल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। तथापि, ग्रामीण और आदिवासी स्कूलों में खेल उपकरणों की कमी, व्यायाम शिक्षकों की रिक्तियाँ, रखरखाव की समस्या तथा शहरी ग्रामीण असमानता अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। 2026-27 राज्य बजट में खेल क्षेत्र के लिए रू 815 करोड़ (जिसमें खेलो इंडिया MP के अंतर्गत रू 230 करोड़) का आवंटन सकारात्मक कदम है। Khelo MP Youth Games ने लाखों छात्रों को प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। अध्ययन सुझाव देता है कि स्कूल-आधारित स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का निर्माण किया जाए, NEP-2020 के साथ पूर्ण एकीकरण किया जाए तथा डिजिटल निगरानी प्रणाली विकसित की जाए ताकि समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके।

© 2026 The Author(s). Published by IJCOPE Journal. Website: https://ijcope.org/

प्रस्तावना (Introduction)

भारत में खेल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के लिए वर्ष 2000 के बाद कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की गईं। राष्ट्रीय खेल नीति 2001 ने खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग घोषित किया। मध्यप्रदेश में 2005 की राज्य खेल नीति ने विद्यालयों को खेल विकास का प्रमुख आधार बनाया। इस नीति में स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड, व्यायाम शिक्षक नियुक्ति तथा खेल मैदान की अनिवार्यता जैसे प्रावधान शामिल थे। वर्ष 2017 में शुरू हुई खेलो इंडिया योजना ने स्कूल स्तर पर खेल को नई गति दी। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य एवं मूल्यांकित हिस्सा बनाने का स्पष्ट निर्देश दिया। इन नीतियो ं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लगभग 25 वर्ष बाद मध्यप्रदेश के विद्यालयों में खेल सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है- 2000 के बाद लागू खेल नीतियों एवं योजनाओं के अंतर्गत विद्यालयों में विकसित खेल सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन करना। शहरी, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता में अंतर का विश्लेषण करना।

बजट आवंटन, क्रियान्वयन स्तर तथा प्रमुख कमियों की पहचान करना। भविष्य की प्रभावी नीति निर्माण के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना। यह मूल्यांकन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अच्छी खेल सुविधाएँ न केवल विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता तथा राष्ट्रीय एकीकरण को भी मजबूत करती हैं।

साहित्य समीक्षा (Literature Review)

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल में 40 मिनट का अनिवार्य खेल पीरियड, व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति तथा नये स्कूल निर्माण के समय खेल मैदान की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल विकास पर विशेष जोर दिया गया। खेलो इंडिया योजना (2017) के अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्तमान में लगभग 52-55 Khelo India Centres संचालित हैं। राज्य में Khelo India State Centre of Excellence तथा 17 Accredited Academies कार्यरत हैं, जिनमें एथलेटिक्स, शूटिंग, हॉकी, जूडो आदि खेलों की ट्रेनिंग दी जा रही है। Samagra Shiksha अभियान के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों को रू 5000 तथा माध्यमिक स्कूलों को रू 25000 प्रति वर्ष खेल उपकरण अनुदान प्रदान किया जाता है। हालिया बजट रिपोर्ट (2025-26) के अनुसार खेल अधोसंरचना पर रू 643.97 करोड़ व्यय प्रस्तावित था, जिसमें 24 निर्माण पूर्ण, 17 निर्माणाधीन

तथा 31 स्वीकृत परियोजनाएँ शामिल थीं। एक महत्वपूर्ण अकादमिक अध्ययन (Mishra & Mehta, 2018) ने 198 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का सर्वेक्षण किया और पाया कि सुविधाओं में कुल वृद्धि हुई है, किंतु ग्रामीण सरकारी स्कूलों में खेल मैदान, उपकरण तथा शिक्षकों की उपलब्धता निजी स्कूलों की तुलना में काफी कम है। इन सभी स्रोतों से स्पष्ट होता है कि नीतियाँ और बजट दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन क्रियान्वयन की गुणवत्ता और समावेशिता अभी भी चुनौती बनी हुई है।

शोध पद्धति (Methodology)

अध्ययन का प्रकार : मूल्यांकनात्मक अध्ययन (Evaluative Study based on Secondary Data)

डेटा संग्रह के प्रमुख स्रोत : मध्यप्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (dsywmp.gov.in) तथा वार्षिक रिपोर्ट।

- 2005 राज्य खेल नीति का मूल दस्तावेज ।
- राज्य बजट दस्तावेज 2025-26 एवं 2026-27 ।
- खेलो इंडिया डैशबोर्ड रिपोर्ट तथा Operational Guidelines
- Samagra Shiksha अभियान के दिशा-निर्देश ।
- पूर्व प्रकाशित अकादमिक अध्ययन (Mishra & Mehta, 2018) ।

क्षेत्र : पूरे मध्यप्रदेश राज्य के 50 जिलों से उपलब्ध जिला-स्तरीय तथा राज्य-स्तरीय द्वितीयक डेटा ।

विश्लेषण विधि : गुणात्मक विश्लेषण नीति प्रावधानों की तुलना वर्तमान वास्तविक स्थिति से।

मात्रात्मक विश्लेषण : बजट आवंटन, केंद्रों / स्टेडियमों की संख्या, निर्माण प्रगति, ग्रामीण शहरी अनुपात तथा शिक्षक रिक्तियों का प्रतिशत विश्लेषण ।

डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए केवल सरकारी प्रकाशनों और प्रतिष्ठित अकादमिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। विश्लेषण एवं परिणाम (Data Analysis & Results)

वर्तमान स्थिति : राज्य में सैकड़ों जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मिनी स्टेडियम तथा इनडोर हॉल विकसित हुए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर आदि शहरों में आधुनिक सिंथेटिक ट्रैक उपलब्ध हैं। राज्य स्तरीय अकादमियाँ (एथलेटिक्स भोपाल, शूटिंग भोपाल, हॉकी ग्वालियर आदि) स्कूल स्तर की प्रतिभाओं को नियमित प्रशिक्षण दे रही हैं।

योजनाओं का प्रभाव : खेलो इंडिया योजना ने ग्रामीण स्कूलों में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को बढ़ावा दिया। Khelo MP Youth Games 2025-26 में लाखों छात्रों को प्रतिस्पर्धा का प्लेटफॉर्म मिला, जिससे स्कूल स्तर पर खेल संस्कृति मजबूत हुई। Samagra Shiksha के अंतर्गत उपकरण अनुदान से कई स्कूलों में बेसिक खेल सामग्री उपलब्ध हुई।

कमियाँ : 2018 के अध्ययन के अनुसार ग्रामीण सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा सुविधाएँ निजी स्कूलों से काफी कम हैं। उपकरणों का रखरखाव, व्यायाम शिक्षकों की रिक्तियाँ (कई जिलों में 30-40 प्रतिशत) तथा नियमित निगरानी की कमी प्रमुख समस्या बनी हुई है। आदिवासी जिलों (शहडोल, अलिराजपुर, जबलपुर आदि) में स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण है।

बजट मूल्यांकन : 2026-27 में खेल क्षेत्र के लिए कुल रू 815 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह वृद्धि सकारात्मक है, किंतु स्कूल - विशिष्ट हिस्से को बढ़ाने तथा उपयोग दर की निगरानी की आवश्यकता है।

चर्चा (Discussion)

मध्यप्रदेश में खेल नीतियाँ और योजनाएँ अच्छी हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन में काफी अंतराल है। शहरी क्षेत्रों में सुविधाएँ अपेक्षाकृत बेहतर हैं, जबकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र अभी भी पिछड़े हुए हैं। खेलो इंडिया और NEP-2020 दोनों ने स्कूल स्तर पर खेल को प्राथमिकता दी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर समन्वय और निगरानी की कमी के कारण पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। बजट वृद्धि सकारात्मक है, किंतु यदि इसे स्कूल आधारित फंड और शिक्षक भर्ती के साथ जोड़ा जाए तो बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव (Conclusion & Recommends)

मध्यप्रदेश के विद्यालयों में खेल सुविधाओं की वर्तमान स्थिति पिछले 25 वर्षों में सुधर रही है। 2005 खेल नीति, खेलो इंडिया तथा Samagra Shiksha जैसी योजनाओं ने आधारभूत ढांचे का विकास किया है। राज्य स्तरीय अकादमियाँ और Khelo MP Youth Games ने स्कूल प्रतिभाओं को नई दिशा दी है। तथापि, पूर्ण

समावेशी विकास के लिए निम्न सुझाव दिए जाते हैं-

- प्रत्येक स्कूल के लिए अलग "स्कूल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान।
- व्यायाम शिक्षकों की रिक्तियों को शीघ्र भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान।
- NEP-2020 के साथ पूर्ण समन्वय कर खेल को पाठ्यक्रम का अनिवार्य एवं मूल्यांकित हिस्सा बनाना।
- GIS आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करना ताकि प्रत्येक स्कूल की सुविधाओ ं की रीयल टाइम निगरानी हो सके।
- ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज तथा स्थानीय खेलों (मल्लखंब, कबड्डी आदि) को प्रोत्साहन।
- निरंतर प्रयास, बेहतर समन्वय और प्रभावी निगरानी से मध्यप्रदेश के विद्यालयों में खेल सुविधाए ँ समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और विद्यार्थी केंद्रित बनाई जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- **मध्यप्रदेश खेल नीति 2005 (mpcharaiveti.com)**
- Directorate of Sports & Youth Welfare, MP (dsywmp.gov.in)
- Khelo India Scheme Reports, Ministry of Youth Affairs & Sports
- Budget Documents 2025-26 & 2026-27, Madhya Pradesh Government
- An Analysis on the Growth of Physical Education Facilities (Ignited.in, 2018)
- Samagra Shiksha Abhiyan Guidelines

About the Authors

शोधार्थी - संजीव कुमार पाण्डेय

संजीव कुमार पाण्डेय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश) के शारीरिक शिक्षा विभाग में शोधार्थी हैं। इनकी रुचि शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान में है। विभिन्न शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता के साथ ये गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य कर रहे हैं।

करस्पॉन्डिंग ऑथर - प्रो. पवन कुमार पचौरी

प्रो. पवन कुमार पचौरी कुलभास्कर आश्रम पी.जी. कॉलेज, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) के शारीरिक शिक्षा एवं योग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। वे एक वरिष्ठ शिक्षाविद्, शोधकर्ता एवं अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रों के लेखक हैं। शारीरिक शिक्षा, योग एवं खेल विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं शोध योगदान के लिए वे व्यापक रूप से प्रतिष्ठित हैं।

डॉ. संजीव मिश्राडॉ.

संजीव मिश्रा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश) के शारीरिक शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। शिक्षण, शोध एवं अकादमिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान से संबंधित अनेक शोध कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है।

शोध पर्यवेक्षक - डॉ. नीलम श्रीवास्तवडॉ.

नीलम श्रीवास्तव वैष्णवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रीवा (मध्य प्रदेश) की प्राचार्या एवं अनुभवी शिक्षाविद् हैं। शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक अनुसंधान तथा अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके मार्गदर्शन में अनेक शोधार्थियों ने सफलतापूर्वक शोध कार्य पूर्ण किए हैं।